

(c) whether there is any proposal under consideration for providing easy and cheaper credit to educated unemployed for starting their own industries; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Some of the small units set up by the technically qualified young men in Delhi under self-employment schemes are reported to be sick on account of a variety of factors such as mismanagement, diversion of funds, shortage of raw material and lack of demand for their products.

(b) Having regard to the prospective viability of the units, banks draw up suitable nursing programmes and make efforts to rehabilitate the sick units.

(c) and (d). Public sector banks are, by and large, financing educated unemployed persons under special schemes formulated for the purpose, on liberalised terms. As such, advances form part of the priority sector, they are exempt from the operation of the minimum lending rate of interest prescribed by Reserve Bank of India.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में चयन किये गए अधिकारी और कर्मचारी

3620. श्री मही लाल : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणीवार कितने अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किये गये और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं और चयन का क्या मानदण्ड अपनाया गया ;

(ख) क्या उपरोक्त बैंकों ने लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात् चयन किये गये उम्मीदवारों की सूचियाँ प्रकाशित नहीं की थीं ;

(ग) क्या इन बैंकों के सम्बन्धित अधिकारियों ने इन चयन सूचियों की अवहेलना की है और अपने मनचाहे व्यक्तियों को मनमाने ढंग से नियुक्त किया है ;

(घ) क्या नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये पदों के आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुये भविष्य में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में आरक्षण हेतु बैंकिंग सेवा आयोग नियुक्त करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) वर्ष 1974-1975 और 1976 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई भर्ती से सम्बन्धित यथा उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या LT 713/ [77]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना ऐसे छः बैंकों को अक्टूबर, 1975 में खोलने के साथ ही शुरू की गई थी। आरम्भ में इन बैंकों में प्रायोजक बैंकों द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराया गया था जिसकी भर्ती नियमों आदि को अन्तिम रूप देने के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सीधी भर्ती करके अपने स्टाफ द्वारा बदला जाना था। अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से सम्बन्धित सरकारी हिदायतें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुपालन के लिए प्रेषित कर दी गई हैं। इन बैंकों में वर्ष 1976 में हुई भर्ती के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सूचना दी है कि प्रायः चुने गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित नहीं की जाती परन्तु चुने गये उम्मीदवारों को अलग से सूचना भेज दी जाती है। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंकों में नियुक्तियां करते समय किसी भी चुने गये उम्मीदवार की उपेक्षा नहीं की गई है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतताओं को ध्यान में रखते हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अर्हता और अर्हक-स्तरों में इन वर्गों के उम्मीदवारों को छूट देने रहे हैं। आरक्षित रिक्तियों की बकाया को भरने के लिए, कुछ बैंक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ही लिपिकीय परीक्षाएँ लेते रहे हैं।

(ङ) बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1975 (1975 का 42) के उपबन्ध क अधीन 21 फरवरी, 1977 से बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना की गई है।

**Misuse of authority by officials of Hotels managed by India Tourism Development Corporation**

3621. DR. BAPU KALDATY: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether several complaints have been received with regard to misuse of authority by the officials of the Hotels managed by India Tourism Development Corporation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps have been taken against those officials for the misuse of the authority?"

**THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK):**

(a) to (c). Complaints against certain officials of the India Tourism Development Corporation containing allegations relating to misuse of authority/ official position in the matter of award of contracts, purchase of stores and material, recruitment of staff, use of staff cars, use of various hotel services and facilities as well mis-appropriation of money and stores, etc. have been received. Some of these complaints are being investigated departmentally and others by the CBI. The question of taking action against the officials concerned will arise only after the findings of the departmental/CBI investigations are known.

**Abolition of Service Charges collected by the Barytes Exporters**

3622. SHRI K. OBUL REDDY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state whether Government propose to abolish 2 per cent service charges now being collected from the barytes exporters, as they are not doing any service regarding the export of barytes?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): No, Sir. Keeping in view the export prices being obtained and the costs, the two per cent service charge is considered reasonable. M.M.T.C. is making international market studies and is helping in better unit value realisation on barytes exports.

**Excise duty on Cigarettes**

3623. SHRI KANWAR LAL GUPTA, Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state: